approximate time limit I have given. With regard to the later part of the question, which is about the change of individual attitude, I submit that we have inherited this file culture from the British period. The attitude of file-making has to be changed in a collective manner. All aspects have to be changed in a collective manner.

Retirement age of Central Government Employees

*22. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Fifth Central Pay Commission had recommended the enhancement of the retirement age of the Central Government employees from the present 58 years to 60 years;

(b) if so, whether Government propose to accept and implement this recommendations; and

(c) If not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE) SHRI R. JANARTHANAM): (a) Yes, Sir.

(b) This recommendation has been accepted by Government in May, 1998 and necessary orders have been issued. The age of retirement in the Armed Forces and the Central Para Military Forces has also been decided to be raised by two years.

(c) Does not arise, in view of (b) above.

श्री ओम प्रकाश कोहली: सभापति महोदय, जिस समय मैंने यह प्रश्न भेजा था उसके बाद केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला किया जिसके लिए मैं केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं और एक प्रकार से जिस उद्देश्य से प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर केन्द्र सरकार ने अपने एक्शन द्वारा, अपने कृत्य द्वारा दिया है। तो भी मैं दो पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक पूरक प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर देने के केन्द्र सरकार के फैसले के परिणामस्वरूप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंकिंग, विश्वविद्यालयों और कालेज क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा भी सेवा निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की मांग उठायी जा रही है? क्या विभिन्न राज्यों के कर्मचारी भी अपनी सेवा निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला करते समय राज्य सरकारों से भी परामर्श किया था या नहीं?

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): सभापति जी, आयु की सीमा बढ़ाने की सिफारिश वेतन आयोग ने भी दी थी। उसको स्वीकार कर लिया गया है। उसके साथ-साथ भर्ती की आयु भी दो साल बढ़ायी गयी है जिससे कोई घाटे में न रहे। प्रदेश सरकारें और अन्य स्वशासी संस्थाएं अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनके लिए वित्तीय कठिनाई पैदा होगी तो हम जानते हैं कि वे केन्द्र सरकार के पास आएंगे और उस पर, आने पर विचार किया जाएगा।

श्री ओम प्रकाश कोहली: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि सेवा निवृत्ति की आयु सीमा दो वर्ष बढ़ा देने का स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना पर क्या असर पड़ेगा? क्या सेवा निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाए जाने से कर्मचारियों को होने वाले लाभों के मद्देनजर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना कम आकर्षक नहीं हो जाएगी और क्या इसको अधिक आकर्षक बनाने का सरकार का कोई इरादा है या नहीं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं नहीं समझता कि इससे आकर्षण कम हो जाएगा। जो स्वेच्छा से निवृत्ति लेना चाहते हैं वे फिर भी स्वेच्छा से निवृत्ति लेंगे।

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, the answer given by the honourable Minister is very vague. Specifically I want to know how many persons are getting extension of service by virtue of extending the retirement age from 58 to 60. And, will it not affect the job opportunities for the unemployed young generation? And, apart from that, Sir, I would like to know whether this order is applicable to the quasi-governemnt Corporations and Boards? I have received telephone calls from my friends from the Chennai Food Corporation of India that 47 employees of the Food Corporation of India are going to retire tomorrow. But the Food Corporation of India has not yet received

any information from the Government with regard to the extension of service from 58 to 60. Therefore, I would like to know whether it will be applicable to the quasi-government organisations and whether it will also be applicable to the Union Territory employees. What is the amount going to be incurred by the Government?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: All public sector undertakings have been covered so far as this decision is concerned. If there are any other public utility services or public organisations, their case will be considered separately.

MR. CHAIRMAN : Dr. Manmohan Singh.

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, through you I would like to ask honourable Prime Minister about the savings in expenditure which are going to be realised as a result of this decision in the year 1998-99.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, वर्तमान अनुमानों के अनुसार इस निर्णय से 5,000 करोड़ का लाभ होगा, बचत होगी,

श्रीमती कमला सिन्हा : सर, मैं प्रधान मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि यह कदम जो इन्होंने पे-कमीशन की रेकमेंडेशन के आधार पर उठाया है आज की थिति में क्या यह रेट्रोगेटिव स्टैप नहीं है? क्योंकि हमारे देश में निरंतर बेकारी बढ़ती जा रही है। आज के दिन में हिन्दुस्तान में लगभग 8 करोड़ नौजवान बेकार हैं अनएजुकेटेड अनएंप्लायड यूथ। तो इससे केवल सरकारी कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाने के कारण डेढ़ लाख लोगों का एम्प्लायमेंट एवेन्यु ब्लॉक हो गया और यह विद इमीडिएट इफेक्ट ऐसा हुआ है। इन्होंने कहा है कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में भी किया है और जो क्वासी गवर्नमेंटल एजेंसीज़ है उनमें भी अगर होगा तो टोटल 23-24 लाख लोग वहां काम करते है, तो इसमें भी अगर हो गया तो उसके फलस्वरूप 5-7 लाख एम्पलायमेंट जो हर साल होते थे उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। 60 साल होने से क्या उसकी एफीशिएंसी भी बढ़ जाती है? मुझे तो लगता है कि यह बहुत ही गलत कदम हुआ है। तो क्या सरकार इस पर कंसिडर करेगी कि क्या इस कदम से और इस तरह से केवल पांच हजार करोड़ रुपये की बचत के लिए देश को पीछे धकेल देना रेट्रोगेटिव स्टैप लेना क्या यह उचित हुआ है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, यह निर्णय बहुत सोच-विचार करने के बाद लिया गया है। वेतन आयोग ने पहले इस पर विचार किया। इस पर संसद् के सदस्यों ने विचार किया। अनेक संसद सदस्य मुझसे मिले। उन्होंने प्रतिवेदन दिए कि वेतन आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली जानी चाहिए। केन्द्रीय कर्मचारी भी इसी मत के थे कि इस तरह का सरकार निर्णय करे। बेरोज़गारी दूर करने का उपाय केवल सरकारी नौकरी नहीं है। आज भी 3 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, जैसे व्यक्ति आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं। सरकारी नौकरी के बाहर रोजगार के आकर्षण बढ़ रहे हैं। यह एक अच्छा चिह्न है। जो भर्ती हो जाते है, व फिर अपने को रिपोर्ट नहीं करते है क्योंकि सरकारी नौकरी में भर्ती होने के बाद उन्हें अच्छा रोजगार, उस से भी अच्छा, बेहतर रोजगार मिल जाता है। तो यह धारणा गलत है कि आयु बढ़ाने से रोजगार के अवसर कम हो जाऐंगे या बेकारी बढ़ जाएगी। बेकारी पर हमला करने के लिए और उपाय अपनाने पड़ेगे। सरकारी दफ्तर में नौकरी पाने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी।

MR. CHAIRMAN: Qusestion No. 23 Shri Balanandan. *(Interruptions)*

SHRI MD. SALIM : Mr. Chairman, this is an attack on the younger generation. *(Interruptions)* The Younger generation is being denied the opportunity. This has serious implications. It is not merely a question of extending it by two years. What will happen to lateral entry? The nation would be denied the experience. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Mr. Salim, please sit down. Mr. Nilotpal Basu, please sit down. I have already called the next question. Shri Balanandan, please.

Determination of Poverty line

*23. SHRI E. BALANANDAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the estimates to determine the ratio of the population living below the poverty line reflects the actual population of the States;

(b) whether Government have any plan to constitute an expert committee or group to go into the matter;